[प्रो० निर्मला कुमारी]

यह उच्चतम दर केवल अतिरिक्त अफीम की मात्रापर ही दी जाएगी, जिस श्रेणी में वह आती है, न कि पूरी अफीम पर। पूर्व की नीति में पैसे तुलनात्मक रूप से कम थे, पर वह पूरी अफीम की मात्रा पर मिलते थे। इस लिए किसान अधिक से अधिक अफीम सरकार को ही ईमानदारी से देना चाहता था।

अब आप के इस स्लैब सिस्टम से कुल मिलाकर जो काश्तकार ईमानदार हैं, अधिक उत्पादन करते हैं, वे नुकसान में रहेंगे। आप किसानों की मेहनत और उनकी मजबूरी को ध्यान में रखें। समय रहते ध्यान दें, वर्ना धीरे-धीरे किसान इस नाजुक तथा परिश्रम - साध्य खेती को छोड़ कर अन्य वाणिज्यिक फसलें बोने लगेगा।

आप कहते हैं कि हमारे पास विश्व बाजार में अफीम नहीं बिक रही है, भारी स्टाक जमा है। क्यों नहीं आप इस दुर्लभ तथा जीवन-रक्षक औषधियों के निर्माण के कच्चे माल को बेचने के लिए विश्व बाजार ढूढते हैं ? राष्ट्रीय औषध निर्माण उद्योगों में भी इसकी खपत बढ़ाई जा सकती है।

(iii) STEPS TO CHECK LAND GRABBING BY ANTI-SOCIAL ELEMENTS IN DELHI.

श्री कुंवर राम (नवादा) : उपध्यक्ष महोदय, असामाजिक तत्वों द्वारा दिल्ली में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वे गरीब मजदूरों को बहका कर जगह जगह खाली स्थानों पर झोंपड़ीयां लगा देते हैं और स्थानीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से उन जमीनों पर पुराना कब्जा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें राशन कार्ड आदि बनवा देते हैं और मतदाता सूची में भी उनका नाम लिखवा देते हैं और बाद में जब सफाई अभियान के दौरान उन्हें उजाड़ा जाता है तो सरकारी नीति के अन्तर्गत उन्हें 25-25 गज जमीन और अन्य सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसका लाभ यदि शहरों के गरीब कामगारों को मिलता तो बेहतर बात होती परन्तु ऐसा नहीं होता। जो असमाजिक तत्व उन्हें जैसे-तैसे जमीन आवंटित कराते हैं वे ही उनसे कई तरह के कागज बनवाकर जमीनों को अपने हाथ में कर लेते हैं और फिर उसे बाजार भाव से बेचते हैं। उसके बाद फिर से किसी दूसरे प्लाट पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं।

अगर दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों का सर्वे किया जाय तो उसके 60-70 प्रतिशत मूल आवंटी पाये जाएंगे और उनकी जमीन, उनका मकान गैर-मजदूरों के हाथ होगा। अधिकांश परिवार पावर आफ एटार्नी अर्थात् मुखतारनामा प्राप्त किए रहते हैं लेकिन सच्चे अर्थ में उस मकान जमीन के खरीदार दूसरे होते हैं। लक्ष्मी नगर और जनकपुरी, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गगनचुम्बी इमारतों का बाजार अर्थात् जिला केन्द्र बनाने का निर्णय लिया है, वहां अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। वहां के मूल आवंटी भी अपने आस-पास की पड़ती जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सूचना मिली है कि लक्ष्मी नगर के राम दास नगर में दो हेक्टेयर भूमि पार्क के लिए सुरक्षित थी जिसका भी अवैध कब्जा कर लिया गया है। पुलिस सूचना दर्ज करने से इन्कार करती है। दिल्ली विकास प्रधिकरण ने भी कोई कार्यवाही नहीं की है। इन क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा रातों रात सैकड़ों झोंपड़ियां खड़ी की जा रही हैं। वे लोग अपने को प्रधान कहते हैं परन्तु वास्तव में वे गुण्डे हैं। आस-पास की जनता को डरा धमका कर झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती बनाने का धंधा कर

हैं । सरकार को राजधानी में एक अभियान चलाकर उन गुण्डों को गिरफ्तार करना चाहिए और अवैध कब्जा हटाना चाहिए !

सच बात तो यह है कि भूमिहीनों के नाम पर वे लोग धंधा कर रहे हैं । उसे दूर किए जाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए और देश में समस्त भूमिहीन मजदूरों की सूची बनाकर, उन्हें एक निर्धारित तिथि को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जमीन का आवंटन किया जाना चाहिए ताकि बिचौलियों और दलालों की दाल न गल सके ।

(iv) NEED FOR EFFECTIVE MEASURES TO CHECK SALINITY OF THE RIVER PERIYAR.

SHRI B. M. BANATWALLA (Pannani): The increasing salinity of the Periyar rive has created a severe crisis in the Cochin. Alwaye industrial belt. The salinity problem has crippled almost all industrial units in the area. Travancore-Cochin Chemicals Indian Rare Earths, Premier Tyres. Hindustan Insecticides and others have been obliged to shut down their plants for the past one week for fear of damage that breakish water may cause to their costly equipments, FACT Udyogmandal division is the worst hit.

The previous UDF Government in Kerala had called a Conference to study the development and take appropriate measures. The Conference was, however, cancelled on the Government tendering resignation.

I urge upon the Government to take immediately effective measures to handle the serious crisis. Appropriate long-term measures will also have to be taken on priority basis.

I request the Government to make a statement in the House as regards measures taken to deal with this serious crisis.

(v) STEPS TO CHECK POLLUTION OF MUVATTUPZHA RIVER.

SHRI K. KUNHAMBU (Cannanore): I want to draw the attention of the Government to a serious situation arising out of the pollution of the Muvattupuzha river caused by the the newsprint factory at Vellor, Kerala. While the setting up of the factory is an important step in the industrial development of Kerala, the essential safety measures against pollution of water, air etc. caused by the factory have to be taken. In the case of newsprint factory at Velloor, there is a growing feeling among the people that the management is not taking adequate steps to save the people from the harmful effects of pollution particularly the water.

Muzattupuzha river is one of those few rivers which have not yet been subjected to the perils of water pollution. Gifted with an abundant supply of crystal clear water throughout the year, this river is the life line of about 3 lakhs of people living in Vaikom. Kanayannoor and Chertalai taluks of Kottayam, Ernakulam and Alleppey districts of Kerala.

The factory is using 40 crore litres of water every day. The treatment plant set up in the factory is mainly intended to control the Oxygen content of the effluent. It is ineffective in removing the most deadly poisonous